बिहार में राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों को ऋण न दिया जाना

4165. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

वित्तमंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे समुदाय के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित लोगों के आर्थिक उपक्रमों को सामान्य रूप से और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से ऋण सहायता के प्रवाह को बढ़ाने के वास्ते प्रयत्न करें । तदनुसार, राज्य सरकार विकास और विस्तार अभिकरणों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगमों द्वारा इन समुदायों के सदस्यों के विकास के वास्ते तैयार की गई विभिन्न अर्थक्षम स्कीमों के क्रियान्वयन में, बैंक, सक्रियता से भाग ले रहे हैं । यह तथ्य कि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, बिहार में, केवल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1981-82 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित 82850 ऋणकर्ताओं समेत कमजोर वर्गों से सम्बन्धित 276169 ऋणकर्ताओं को सहायता दिए जाने का अनुमान है, यह दर्शाता है कि बैंक निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उस राज्य में भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं ।

Managerial Deficiency in Banks

4166. SHRI SURYA NARAYAN SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is it a fact that viewed from talents, experience and maturity, the management of small-sized banks is sub-standard;

(b) is it also a fact that this managerial deficiency is more pronounced in the banks nationalised on 15th April, 1980;

(c) is it true that Government have decided to effect inter-bank transfer of senior executives with a view to bringing up the standard of management in these banks; and

(d) if so, when this scheme is likely to be put in operation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): (a) to (d). At times, one or the other Banks may experience management gaps at certain levels but it would not be appropriate to single out any particular Bank in this respect. The Committte for standardisation of pay scales, allolwances and perquisites of officers in the nationalised banks, commonly known as the 'Pillai Committee' had, *inter alia*, recommended that the top executives of the nationalised banks might be transferred from one bank to another to strengthen the staff structure of weaker banks or to meet succession gaps or to remove vested interests. This has, however, to be considered in detail as there are a number of issues involved.